न्यूज़ पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया

NEWSPAPERS ASSOCIATION OF INDIA

Volume XVIII वर्ष 18 | No. 01 अंक: 01 | December-2012 दिसम्बर-2012 | Rs. 5/- per copy

न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का अब तक का सफर

❑ **एन. ए. आई. डेस्क**

न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के द्वारा पत्रकारिता व सामाजिक

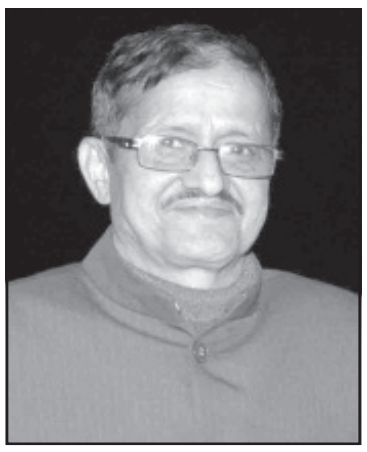

गतिविधियों के क्षेत्र मे एन.ए.आई पुरस्कार 2012 के लिए नामांकन प्रारंभ व न्यूजपेपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया का राष्ट्रीय सम्मलेन 29 दिसम्बर 2012 को कॉन्सीटूयषन क्लब, रफी मार्ग दिल्ली को होगा।

न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया भारत के पत्रकारों व समाज सेविओं को आमंत्रित करता है जिनका सहयोग भारत को विकासशील और प्रगतिशील बनाने मे रहा है और उन कार्यों को लेख, समाचारपत्र, वीडियो, तस्वीरों, सामाजिक गतिविधियों, द्वारा प्रकाशित व प्रसारित किया हो कृषि व ग्रामीण विकास के कार्यों मे अपना सहयोग दिया हो हर साल की तरह इस साल भी न्यूजपेपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया भारत के पत्रकारों व समाज सेविओं को पुरुस्कार से सम्मानित करेगा। न्यूजपेपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया 19 सालों से पत्रकारों की सेवा करने व उनकी समस्यों का समाधान करने पे लगी है पत्रकारिता के क्षेत्र मे कार्य करने वाले लोग देश की जनता की समस्या को सामने लाते है पर अपनी समस्या को किसी से नहीं बताते हैं उन पत्रकारों व समाज सेविओं को सलाम व सम्मान आप अपने प्रकाशित लिखा लेख, समाचार, वीडियो, तस्वीरें, सामाजिक गतिविधियों, कृषि व ग्रामीण विकास पर लघु फिल्म हमे भेजें यदि आप 2012 एन.ए.आई पुरस्कार कार्यक्रम में भाग लेने में रुचि रखते हैं, तो कृपया अपने पोर्ट फोलियो भेजें. या मेल कर सकते हैं – naiindia@gmail.com हमारी वेबसाइट मे सारी जानकारी www.naiindia.com

इस पुरुस्कार कार्यक्रम मे देश के 4 राज्यों के संपादक, प्रकाशक , पत्रकार हिस्सा लेंगे समाचार पत्रों व समाचार जगत मे कार्य करने वाले संपादको , प्रकाशकों , पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी व उनका समाधान कैसे किया जाए सभी सवालों को सरकार के सामने रखा जाएगा व उन सभी समस्यों को हल करने की मांग की जाएगी देश के संविधान की मर्यादा के पालन को लेकर सामाजिक हितो की राष्ट्रीय आवाज बनाने मे लोकतंत्र के चोथे स्थम्ब के रूप मे इस मीडिया शक्ति से बड़ा कोई भी लोकपाल वैकल्पिक जवाबदेही नहीं निभा पा रहा है जिसे जनतंत्र की आवाज कहा जा सके । समाचार पत्रों के प्रतिनिधि समाज प्रहरियों की भूमिका ने हे देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आजतक भारत को विश्व सचेतक बनाने की मंजिल को आसन रास्ता दिया है। मीडिया ने राजनैतिक कोशलता प्रोत्साहित करने मे कई सहायिक कदम उठाए है। इस सम्हारो मे मीडिया के हको की आवाज को उठाने के साथ साथ मीडिया प्रहरियों की सुरक्षा के लिए राज्यों की नीतियों के बदलाव के लिए भी जोर दिया जाएगा।

न्यूजपेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन 29 दिसम्बर 2012 को कन्स्ट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफी मार्ग नई दिल्ली में होगा।

कार्यक्रम की सम्पूर्ण जानकारी पृष्ठ 8 पर देखें

CANCER

Kalpana Karala
[D.Y.N, N.D.D.Y,
M.A (SOL, PRIKSHA MEDITATION YOG), PRANIC HEALER]

The word cancer, comes from the latin "carcinoma' meaning crab. It is today the second largest killer in the world, next only to heart ailments. When the tissue cells of any particular organ start dividing and growing uncontrolled then it is called a "Tumour". Some of the them are life threatening where as some of them are not much harmful. The fatal tumours are known as 'Cancer' and in medical term they are known as "Malignant Tumours". It grows in three stages. When growth starts then it is known as 'Primary tumour'. When this tumour grows further and spreads to other tissues then it is known as 'secondary tumour'. After certain period this tumour ruptures and the malignant cells spread to whole body through blood circulation and the whole body becomes cancerous. This is the end stage of life.

Types of Cancer:

Adenorarcinoma, Osteogenic Sarcoma, Myeloma, Leukemia are various types of cancer.

Dr. Limning Stone - says that "Cancer is the gift of modern civilization:.

❑ Possible reasons of cancer.

1. Food items having artificial colours.
2. Use of strong spices in food items.
3. Use of flavours in food items.
4. Excessive eating.
5. Excessive consumption of non-vegetarian food.
6. Use of contraceptive medicines.
7. Consumption of saccharine.
8. Use of Strong medicines in acute diseases.
9. Delayed healing of surgical injuries.
10. Coal-tar, cement, charcoal, benzenes, paraffin, etc. substances

When come in contact with skin or if enter body via oral route then they create metabolic disturbances giving rise to preduction of harmful toxins.

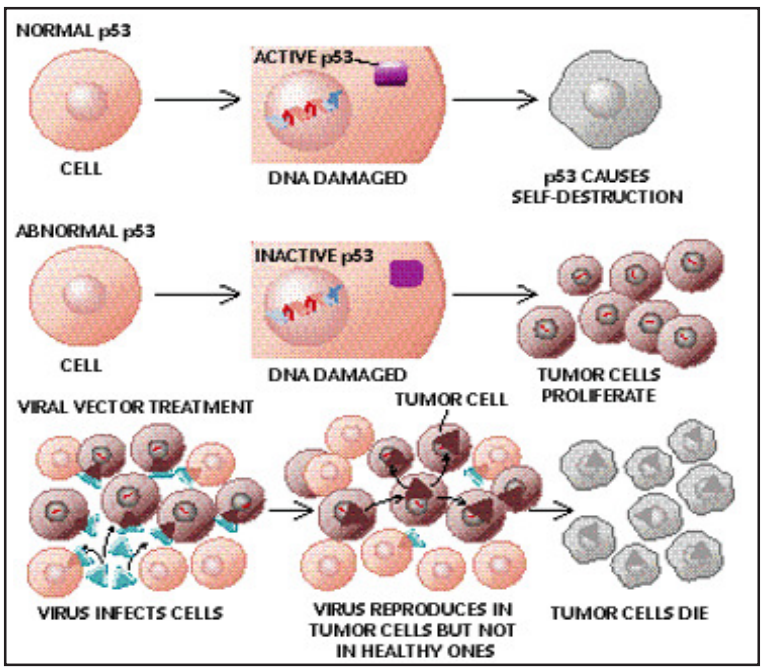

These toxins are the root causes of cancer.

❑ Supportive diet in preduction of cancer.

According to global statistic non-vegetarian people are more vulnerable compared to vegetarian people, because nitrogen containing food is more responsible to contaminate our body which facilitates cancer production.

❑ Irritation and Resentment were considered as the main reason of cancer.

If a particular part of body is irritated constantly then there may arise cancer. Usually neck of womb, lips, tongue, throat, stomach and intestines is more vulnerable. In India, oral cancer in males and uterine cancer in females is more common.

Symptoms: In males, major sites of cancer are lips, throat, tongue, line, liver, chest and intestines. Tongue, throat and lungs are affected in those who smoke excessively. Oral cancers do not heal easily. There is pain around growth. In females mostly breast, cervix, stomach and intestines are affected.

❑ Special Signs of Cancer:

Skin Cancer is hard and takes form of a wound when ruptures. Internal cancer grows in many ways pain is the major symptom in both the cases.

1. Oral cancer is more easily diagnosed compared to others. Mouth does not fully open.
2. Repeated bleeding in women.
3. Difficulty in swallowing.
4. Change in urine and stool habits or constipation.
5. Hoarseness of voice or constant cough.
6. Appearance of a growth ones any part of body especially throat and breast.

❑ ***Treatment:***

Fasting or Juice Fasting should be continued until the disease comes, contro with use of enema once or twice a day according to nee the affected part should be given sunbath daily followed by waist bath, steam bath twice in a month, bandage application over affected part, wet linen wrapping, wet bandage application over lower abdomen every night. Steam application over affected part fo 5-10 minutes and warm clay bandage during rest of the time. If there is no pain or if there is bleeding from the affected part then linen cloth soaked in chilled water should be applied.

❑ Preksha Yoga life style:

People of ancient India used to live a natural life style. Early to rise, asanas, Pranayam, bathing with natural water, praying god, keeping mild nature etc. But by the time all vanished and new diseases were born in our life. But we have to follow an experiment to lead a healthy life, which can be divided as

❑ Yoga therapy, Pranayam, Mudras.

❑ Meditation and Kayotsarg.

❑ Preksha Yoga life style.

❑ Diet Control.

❑ Stress free life.

क्यों ना सिगरेट पर बैन लगाया जाये...?

❑ **अमर कुमार सहनी**

दिल्ली समेत 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश नवम्बर–2012 से गुटखा पर बैन लगने से दिल को थोरी सी राहत मिली हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो गुटखा पर बैन लगाने में नाकाम हैं।

एक तरफ तो गुटखा बंद होने से थोरी राहत तो जरुर पहुची है वही दूसरी तरफ कही न कही एक नया चिंता की बात भी सामने आई हैं।

चिंता की बात यह हैं की बच्चों और यूवाओ का रुख अब धुम्रपान और तम्बाकू उक्त पदार्थो का सेवन पर तेजी से हो रहा हैं। जो की बहुत ही खतरनाक हैं क्यों की धुम्रपान को ही सभी बड़े नशा का शुरुआती मूल आधार माना जाता है। सिगरेट और बीडी जैसे पदार्थ पर लिखे हुए तम्बाकू से कैंसर होता हैं इस के बावजूद भी लोग इनका सेवन वेखौफ हो कर रहे हैं. आपने सभी पनबाड़ी के दुकान पर यह लिखा हुआ तो देखा ही होगा 18 साल से कम उम्र को तम्बाकू बेचना कानून अपराध है इस का मतलव है की 18 से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू युक्त पदार्थ नहीं देना हैं, नहीं तो जुर्माना हो सकता हैं लेकिन ऐसा कभी भी कही नहीं इस नियम का पालन किया जाता हैं. इसका दुष्परिणाम यह हुआ की आज कल तो स्कूली बच्चों को आम रूप से धुम्रपान करते हुए देखा जा सकता है जो की हमारे देश और समाज के लिय बहुत ही घातक है। ऐसे में एक ही प्रश्न मन में उठता है की क्यों ना सिगरेट पर बैन लगया जाय..... ? जिससे हमारे अपने ही समाज को साफ सुथरा रखा जा सके। धुम्रपान से होने वाले कुछ ऐसे खतरनाक बीमारी जिनके कारण भारत में लाखो लोग दम तोड़ देते हैं जिसे सरकार के एक फैसले से आसानी से लाखो लोगो को बचाया जा सकता हैं. कुछ इस प्रकार है – हार्ट अटैक, Struckes Chromic Obstructive Pulmonary Disese (COPD) Emphysema and Cancer जिसमे फेफड़े की कैंसर आम हैं। अब समय आ गया है की हमारे सरकार को एक और मत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिय और धुम्रपान पर पूर्णतः बैन लगा देना चाहिये।

क्या कसूर है बुजुर्गो का ?

पिंकी सिंह

आए दिन हमारे न्यूज चैनल या अखबारों में दिखने और पढ़ने को मिलती है कि एक बुजूर्ग के घर में कुछ अपराधी घुस कर चोरी करके बुजूर्ग की हत्या कर देते हैं, इस पर आश्चर्य नहीं होती है कि फिर किसी बुजूर्ग पर कुछ अपराधियों ने हमला करके उन्की हत्या कर दी। ये अपराध जो हमारे बूजुर्गो के साथ हो रहा है। कब तक होता रहेगा? क्या ये अपराध रुकेगा नहीं ? बूजुर्गो के साथ होने वाली हत्याएँ, डकैती और चोरी इन सभी तरह कि घटनाये दिन–प्रतिदिन पाँव पसारती जा रही है। ये अपराधिक घटनाये थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इन बुजुर्गो के साथ होने वाली घटनाओ का? कही इन पर हो रहे अपराधिक घटनाओ को जिम्मेदार हम समाज में रहने वाले समाजिक व्यक्ति ही तो नही है वो कुछ असमाजिक व्यक्ति जो इन घटनाओ को घटित करते है। उन्हे ऐसे घिनौने कार्य करने का मौका हमारे समाज के व्यक्ति देते है। जब हम अपने बुजुर्गों का ध्यान देना छोडकर अपने काम में व्यस्त हो जाते है और हमारे बुजुर्ग अकेले रह जाते है। हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली) के एक सर्वे के अनुसार 12 प्रतिशत बुजुर्ग बिना अपनों के सहारे बिल्कुल अकेले जिन्दगी जी रहे है। इनमे दिन–प्रतिदिन बढ़ोतरी ही होती जा रही है, जिनमे से 43 प्रतिशत बूजुर्गो के संताने इन्हे सहारा नहीं देते और वे अपने कैरियर बनाने के लिये वे अपने बुजुर्ग माता–पिता को छोड़कर अन्य शहर में या विदेशों में रहने चले जाते है। इसका जीवंत उदहारण है प्रो. शास्त्री जी की हत्या जो की दिल्ली के डिफेन्स कॉलोनी में रहा करते थे। उनके पुत्र विदेश में कार्यरत थे शास्त्री जी अकेले अपने मकान में रहा करते थे उन्होंने दो लड़कों को अपने घर पर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिये रख लिया उन लड़कों को शास्त्री जी ने अपने बच्चों के जैसा प्यार और ख्याल किया पर लडकों ने शास्त्री जी को अकेला देख उनकी हत्या कर सारे सामान लुट कर चम्पत हो गये।

ये तो एक उदहारण है। पर न जाने कितने ऐसे बुजुर्गों की हत्याए हो चुकी है । बुजुर्गों की सुरक्षा हम समाज में रहने वाले लोगों को करनी चहिये और हमारे बुजूर्ग भी अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक रहे वे पुलिस द्वारा उपलब्ध किया गया टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर को हमेशा याद रखे और पुलिस द्वारा दिए गए सलाह को हमेशा अनुसरण करे क्योंकि जब तक ये हमारे बुजुर्ग खुद अपने लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक ये हत्याए, मारपीट, चोरी और धोखा ये सब घटनाए बुजुर्गो के साथ होती रहेगी।

इन्द्र कुमार गुजराल का सफर

शहनवाज़ सैफी

शुरूआती जिंदगी

इंद्र कुमार गुजराल का जन्म 4 दिसंबर 1919 को लाहौर में हुआ। इनकी शुरूआती पढ़ाई लाहौर में ही हुई। उन्होने लाहौर के डी.ए.वी कॉलेज, फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज विश्वविद्यालय में लाहौर से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की तथा इसके बाद उन्होने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया और 1942 में

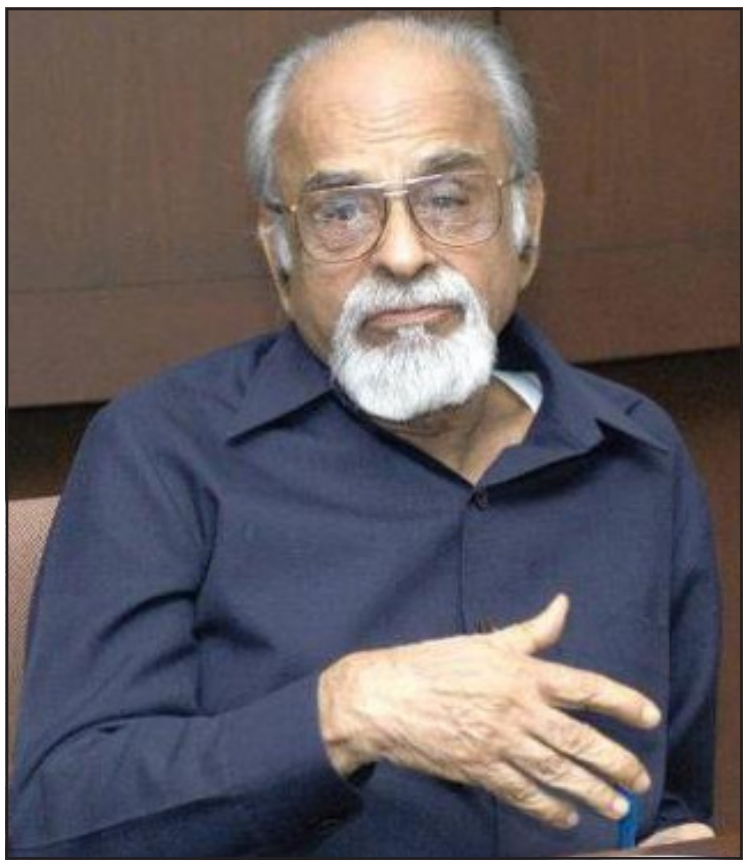

भी गए। इसके पष्चात वह विद्यार्थी के रूप में ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। गुजराल साहब को कविता लिखने का भी षौक था। वह काफी अच्छी उर्दू भी जानते थे तथा लोगो से उर्दू में बाते भी करते थे। वह एक इन्सीटूयषन में एक चान्सलर के रूप में भी कार्यरत रहे। 11 जुलाई 2011 को उनकी पत्नी की मुत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी भी एक प्रषंसित कवियत्री थी। उनका एक बेटा नरेष षिरोमणि अकाली दल के राज्य सभा में सांसद हैं।

राजनीति

गुजराल 1958 में नई दिल्ली नगर समिति के उपाध्यक्ष बने और 1964 में कांग्रेस में शामिल हो गए। वह इंदिरा गांधी के पास गया थे और अप्रैल 1964 में राज्यसभा सांसद बने। जून 1975 के आपातकाल के दौरान, गुजराल सूचना और प्रसारण मंत्री बने थे, जहां उन्होंने भारत में सेंसरशिप के एक समय के दौरान मीडिया के आरोप में किया यह आरोप दूरदर्षन का था। वह फिर से राज्यसभा के लिए 1976 तक सेवा करने के लिए चुना गए थे। उन्होंने यह भी जल संसाधन मंत्री के रूप में सेवा की। बाद में, गुजराल भारत के सोवियत संघ के राजदूत इंदिरा गांधी द्वारा नियुक्त किया गए थे और मोरारजी देसाई और चरण सिंह के कार्यकाल के दौरान पर रुके थे। उन्हें मंत्रालय के बाहर किया गया है साथ ही संघर्ष की वजह से यह सभी अफवाहे थी। प्रधानमंत्री के पुत्र संजय गांधी, मीडिया सेंसरशिप पर, और विद्या चरण शुक्ला, जो इस मामले पर पार्टी लाइन का पालन में कोई हिचक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

जनता दल

गुजराल ने 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था । वह तो जनता दल में शामिल हो गए थे। भारतीय आम चुनाव, 1989 में, गुजराल जालंधर से पंजाब में निर्वाचित किया गया था। वह प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 1989 में सिंह ने श्रीनगर रूबे सईद के 1989 के अपहरण के अपराधियों के साथ बातचीत करने के लिए भेजा। उन्होंने यह भी खाड़ी युद्ध के दौरान विवाद के बारे में लाया जब वह एक शो के अच्छे विश्वास के रूप में सद्दाम हुसैन को गले लगाया के लिए भारतीय सुनिश्चित प्रवासियों सुरक्षित हो । भारतीय आम चुनाव, 1991 में, गुजराल बिहार में पटना से चुनाव लड़ा. होगा. हालांकि, चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप के कारण चुनाव काउंटरमेंडिड किया गया था। 1992

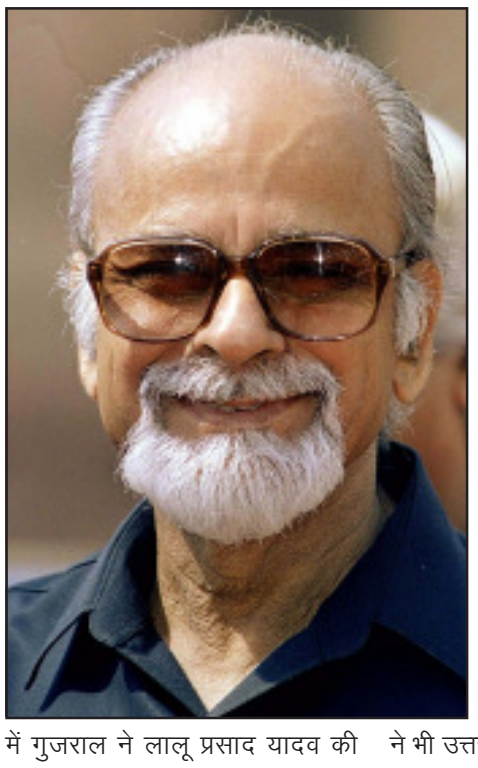

में गुजराल ने लालू प्रसाद यादव की मदद से राज्यसभा के लिए चुना गया

प्रधानमंत्री पद का स्फर

गुजराल दूसरे ऐसे आदमी थे जो कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव के बीच आम सहमति के उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार को बाहर से कांग्रेस द्वारा समर्थित किया गया। अपने कार्यकाल के शुरुआती सप्ताह में केंद्रीय जांच ब्यूरो चारा घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में राज्य के मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने के करने की अनुमति के लिए पूछा। यहां तक कि कानूनी विद्वानों ने कहा कि यादव अभियोजन पक्ष से बच नहीं सकता है। इसके बाद यादव के इस्तीफे की मांग दोनों के भीतर से और संयुक्त मोर्चा के बिना उठाया गया था। संयुक्त मोर्चा और तेलगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत यादव और अन्य राजद के सदस्यों के इस्तीफे के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जाता है, की जद सदस्य शरद यादव, एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा था, जबकि और राम विलास पासवान जो आरोप लगाया राजद के सदस्यों को कांति सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह और कैप्टन जय नारायण निषाद की बर्खास्तगी के लिए बुलाया. हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यादव के इस्तीफे के लिए मामूली कॉल की पेशकश की। यादव तो गुजराल बिहार में किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चलाने के लिए अपने समर्थन पाने के लिए समर्थन की पेशकश की। गुजराल, हालांकि, इस मामले पर चुप था, लेकिन बाद विवादास्पद ढंग से सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह ने यादव के खिलाफ मामले की जांच कर रहे थे बाद में उनका तबादला कर दिया गया, और उसे आर.सी. शर्मा ने कहा गुजराल सीधे सीबीआई नियंत्रण होगा और उस जगह गति निश्चित रूप से कई सनसनीखेज मामलों की जांच की अब शिथिल जाएगा। हालांकि, यादव अभी भी जद नेता शरद यादव द्वारा पार्टी से निष्कासित कर दिया है, 1997 में अपने ही राष्ट्रीय जनता दल के गठन से पहले उनकी सरकार के एक और विवादास्पद फैसला 1997 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश सरकार, कल्याण सिंह के नेतृत्व में. मांगी हिंसा और अनियंत्रित .श्यों के बाद विश्वास का एक वोट विधानसभा में जगह ले ली. हालांकि राष्ट्रपति के.आर. नारायणन सिफारिश पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और इसे वापस भेजा पुनर्विचार के लिए सरकार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ एक निर्णय दिया। उन्होंने यह भी व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया।

28 अगस्त 1997, जैन आयोग की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई थी और 16 को लीक किया गया नवम्बर आयोग ने राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र के पहलुओं में पूछा था और कथित तौर पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की आलोचना नरसिंह राव सरकार के रूप में इस तरह के अन्य लोगों के बीच, मौन रूप से गांधी की हत्या में आरोप लगाया तमिल आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए. द्रमुक केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा था और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की थी. कांग्रेस पहले संसद, जो गुजराल, जो द्रमुक और तमिल मानिला कांग्रेस सरकार की ओर से द्रमुक की वापसी के लिए नेतृत्व करेंगे के बीच एक लड़ाई की आशंका से इनकार कर दिया था की मंजिल पर रिपोर्ट की जंइसपदह की मांग की।

बिमारी और मृत्यु

गुजराल मेदान्ता मेडिसिटी में गुड़गांव, हरियाणा (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा) में भर्ती कराया गया था, 19 नवंबर, 2012 को, फेफड़ों के संक्रमण के साथ का निदान किया जा रहा था बाद में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों पहले एक गंभीर छाती में संक्रमण का सामना करना पड़ा था अस्पताल डायलिसिस के एक साल से भी अधिक के बाद , अस्पताल में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था । नवम्बर 27, वह बेहोश हो गए और उनके मूत्र उत्पादन प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया। गुजराल को 30 नवम्बर 2012 को अपनी बीमारियों के शिकार हो गया। उनके शरीर को राज्य में उनके सरकारी आवास 5, जनपथ पर संपद किया गया था, अगले दिन दोपहर तक. भारत सरकार ने 6 दिसंबर तक एक सात दिन की अवधि के राजकीय शोक और सरकारी समारोहों में रद्द घोषित कर दिया गया था । वह 15रू पर एक राज्य के अंतिम संस्कार दिया गया था । दिसम्बर समता स्थल के निकट है. उसकी मौत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, जिसके बाद दोनों सदनों को स्थगित कर दी द्वारा संसद में घोषणा की थी। 3 उसे दिसम्बर शोक संदर्भ के लिए आयोजित किया जाएगा।

कानून मंत्री अश्विनी कुमार, वीरप्पा मोइली, गुलाम नबी प्रतिक्रियाओं अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अन्य तत्काल प्रतिक्रियाओं सांसदों से आया आजाद. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा डॉ. फारूक अब्दुल्ला के लिए मंत्री अपनी संवेदना की पेशकश की थी और कहा कि गुजराल एक राजनीतिज्ञ, एक राजनयिक और एक मानवतावादी जो राजनयिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपने कई उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा, जबकि रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्रीकांत कुमार जेना ने कहा कि गुजराल एक असाधारण व्यक्तित्व, साहस और बुद्धि आदमी थे । आज हम अत्यंत पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदर कुमार गुजराल, जो असाधारण साहस और बुद्धि का एक आदमी थे। इनके निधन पर दुखी महसूस यूनियन कैबिनेट ने एक बयान दिया था कि जारी उनकी मृत्यु में, भारत एक महान देशभक्त, एक दूरदर्शी नेता और स्वतंत्रता सेनानी खो दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुजराल के बेटे, सांसद नरेश गुजराल ने लिखा हैं। दिवंगत नेता सद्भावना और राजनीतिक स्पेक्ट्रम भर दोस्ती को जीतने की क्षमता है यह इन गुणों और उनके व्यक्तित्व का असली गर्मी है कि उसे व्यापक रूप से इस तरह के एक बनाया है. प्रशंसा और सम्मान भारत के प्रधानमंत्री, सांसद और राजदूत श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक संदेश भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा की श्री गुजराल एक तेजी से वैश्वीकरत दुनिया में अपने समय से आगे थे। श्रीलंका हमेशा भारत – श्रीलंका संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में आभार श्री इंद्रकुमार गुजराल योगदान के साथ याद होगा। पाकिस्तानी प्रधान मंत्री राजा परवेज अशरफ गुजराल भारत – पाकिस्तान संबंधों को बढ़ाने में सराहनीय भूमिका उल्लेख किया है, जबकि वह यह भी कहा कि दक्षिण एशिया एक महान और प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ खो दिया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंतिम संस्कार के लिए उसे अवामी लीग पार्टी के एक अनाम वरिष्ठ नेता भेजा सलमान खुर्शीद और लाल .ष्ण आडवाणी उसके अंतिम संस्कार में गणमान्य व्यक्तियों के बीच थे।

सम्पादकीय

शहरियों के साथ भी हुआ छलावा

❑ विपिन गौड़

गांव वालों को ठगा जा रहा है तो शहर वाले भी छलावे का शिकार हो रहे हैं। यह खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की हाल ही में संसद में पेश एक रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट शहरों में सुविधाएं देने, विशेषकर मलिन बस्तियों की दशा सुधारने वाली जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के बारे में है। केन्द्र सरकार की शहरी क्षेत्र में ढांचागत विकास की यह उतनी ही महत्वपूर्ण योजना है जितनी ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा की। मनरेगा में एक बटा चार अंश भी काम नहीं हुआ लेकिन ग्रामीण फिर भी राहत महसूस कर रहे हैं। यूपीए सरकार को दूसरी पारी खेलने में इसी योजना ने भरपूर मदद पहुंचाई थी। इसी की तर्ज पर केन्द्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम योजना लागू की जो शहरों में ठीक कार्यान्वित नहीं की जा सकी। इसके तहत आधा–अधूरा काम हुआ और नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 115 करोड़ रुपये तो खर्च ही नहीं किये गये जबकि इसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जैसी बात नहीं थी। शहरियों के साथ छल करने में केन्द्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं जो आये दिन यह आरोप लगाती हैं कि केन्द्र सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और अभी हाल में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता ने यह आरोप लगाया था।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने केन्द्र सरकार की शहरी क्षेत्र में आधारभूत सुधार की महत्वाकांक्षी योजना जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में ढेरों खामियां गिनाते हुए अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी है। कैग की कई रिपोर्टों ने यूपीए सरकार को कठघरे में खड़ा कर रखा है और इसी के बाद कांग्रेस की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया कि न्यायमूर्ति शुंगलू समिति की सिफारिशों के अनुरूप कैग को भी चुनाव आयोग की तरह बहुराष्ट्रीय बना दिया जाए। इसके पीछे कैग की रिपोर्टों में छिपा तीखापन ही है। मनरेगा को लेकर भी कैग ने कई शिकायतें कीं। केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं में त्रुटियां देखकर कैग ने उंगली उठाई है। अब केन्द्र सरकार की शहरी क्षेत्र में ढांचागत विकास की परियोजना का एक कड़वा सच सामने रखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस परियोजना के लिये आवंटित राशि में से लगभग 115 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किये गये और जिन कार्यों में रुपये खर्च हुए, वे भी आधे–अधूरे हैं। इस प्रकार केन्द्र सरकार इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से शहर के लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकी। मनरेगा की तरह ही जेएनएनयूआरएम योजना में भी उन लोगों को लाभ पहुंचाने की शिकायत कैग को मिली जो इसके पास नहीं है हालांकि इससे व्यक्तिगत लाभ की जगह सामूहिक लाभ ज्यादा है। मसलन शहरों में सिटी बसें चलायी गयी हैं जो सभी के काम आती हैं। इन बसों पर जेएनएनयूआरएम लिखा भी रहता है लेकिन गरीबों के लिये आवास जैसे कार्यक्रम का लाभ गरीबों की जगह दूसरे लोगों को मिला तो इसमें राज्य सरकारों की भूमिका पर संदेह पैदा होता है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय जेएनएनयूआरएम जैसी परियोजना की निगरानी करने में सक्षम भी नहीं हैं। संसद में गत 29 नवम्बर को पेश की गयी कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस परियोजना के तहत मंजूरी प्राप्त 1517 परियोजनाओं में से केवल 22 ही मार्च 2011 तक की निर्धारित अवधि में पूरी जा जा सकीं, बाकी का काम आधा–अधूरा रहा जिससे लागत राशि भी बढ़ गयी है। परियोजनाओं के बारे में संक्षिप्त में विवरण देते हुए कहा गया कि जेएनएनयूआरएम के तहत 1517 आवासीय तथा 1998 बुनियादी ढांचा सुधारने की परियोजनाएं वर्ष 2005 में शुरू की गयी थीं। इनका कार्यकाल 2011 तक था लेकिन 31 मार्च 2011 को जो रिपोर्ट मिली है उसमें सिर्फ 22 आवासीय परियोजनाएं पूरी की गयीं। रिपोर्ट में कहा गया कि स्वीकृत मकानों में केवल 26 फीसद ही बनकर पूरी तरह तैयार हैं। इसी प्रकार बुनियादी ढांचा में सुधार के मामले में भी स्वीकृत 1298 परियोजनाओं में केवल 231 ही पूरी हो पायी हैं। यह योजना केन्द्र सरकार की है और शहरी विकास एवं आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की देख रेख में चल रही हैं। काम राज्यों के अधीन होते हैं अर्थात् कार्यदायी संस्था की भी ढिलाई रहती है। कैग का यह आरोप, एक बार पुनः राज्य सरकारों की नीयत पर संदेह पैदा करता है कि शहरी गरीबों के लिये मकानों के आवंटन में अपात्र लोगों को लाभ मिला। कैग ने कहा है कि अनाधिकृत और अनियमित खर्च, ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के भी कुछ मामले सामने आये हैं। यह भी कहा गया कि केन्द्र सरकार से धन मिलने में देरी के चलते भी कई योजनाएं लम्बित हुईं। रिपोर्ट में बताया गया है कि योजना आयोग ने इसके लिये 66084.66 करोड़ रुपये का आवंटन किया था जबकि केन्द्र सरकार ने सिर्फ 37070.15 करोड़ ही आवंटित किये। अर्थात् पूरी राशि नहीं मिली। कैग की रिपोर्ट बताती है कि कुछ राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधार नहीं किये गये जबकि राज्यों ने केन्द्र सरकार से इस प्रकार का वादा किया था। इसलिए केन्द्र सरकार से पूरी धनराशि नहीं जारी की गयी। सरकारों के बीच का यह झगड़ा हो या खेल लेकिन प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है। आम आदमी को एफडीआई और स्पेक्ट्रम आवंटन से ज्यादा जरूरत इन्हीं सुविधाओं को ईमानदारी से लागू करने की है। अफसोस कि केन्द्र और राज्य दोनों की सरकारें जनता से छलावा कर रही हैं।

भारत में अनूठा जनतंत्र

❑ दिलीप कुमार

विभाजन के वक्त पूरे देश की आबादी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलाकर 33 करोड़ थी और आज भारतीय गणना के अनुसार सौ करोड़ से अधिक है। भारतीय राजनीतिक पार्टियां देश के हित को नजरअंदाज करते हुए भारतीय नागरिकता कानून को महत्व नही देती है फलस्वरूप देश की सीमाओं से लगे हुए सभी अप्रजातांत्रिक देश के नागरिक हमारे चुनाव प्रक्रिया में बिना किसी परेशानी के शामिल हो जाते हैं और यहां की ढुल–मुल व्यवस्था के चलते सभी सुविधाएं भारतीय नागरिक के रूप में प्राप्त कर लेते है। भारतीय जनतंत्र विविध राजनीतिक पार्टी व्यवस्था पर आधारित है क्यूंकि संविधान रचयिताओं का यह प्रयत्न था कि प्रजातंत्र का फल प्रत्येक भारतीय तक पहुंचना चाहिए क्यूंकि बीते हुए 800 वर्षों में साधारण नागरिक को यह अधिकार नही प्राप्त हुआ कि अपने हुक्मरानों का चुनाव वह स्वयं कर सके, ऐसी सुव्यवस्था में एक भयंकर कमी अशिक्षित जनता है जिसे सरलता से धर्म, जाति एवं आरक्षण के नाम पर बहकाया जा सकता है जिसका परिणाम वोटों पर पड़ता है और इस कार्य में हमारे आधुनिक नेता बहुत निपुण समझे जाते हैं उदाहणस्वरूप हाल ही में गुज्जर समुदाय का आरक्षण संबंधित विरोध के चलते देश की करोड़ों की सम्पित्त स्वाहा तो हुई ही व वसुंधरा राजे की सरकार का भी पतन हो गया। विविध राजनीतिक पार्टी ढर्रा होने के कारण कोई भी समूह कुछ विचारों को एकमत करके एक राजनीतिक पार्टी का रूप दे सकती है और जीतने के बाद इच्छानुसार बिखर भी सकती है। इस व्यवस्था में निर्दलीय सदस्यों की स्थिति अति भयावह है, क्यूंकि उनकी ईमानदारी किसी तरफ नही होती बल्कि अपनी स्वार्थपूर्ति होती है और वर्तमान परिपेक्ष्य में भारतीय राजनीति में वह एक मूल्यवान एवं बिकाऊ वस्तु है। साधारणतरू स्थानीय मामलों के कारण निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाते हैं और जीत जाने के उपरान्त परिस्थिति के अनुसार अपना मोल भाव करते है, आम जनता को यह समझना चाहिए कि स्थानीय मामला यदि किसी नामचीन राजनीतिक पार्टी द्वारा उठाए जा रहा हो तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है बनिस्बत निर्दलीय प्रत्याशी के।जनादेश प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण अधिकार है परन्तु इसको सुव्यवस्थित रूप से कार्यरत करना आवश्यक ही नही बल्कि जनतंत्र को सफल बनाने का प्रथम चरण है। हमारे देश में 18 वष की आयु के प्रत्येक नागरिक को जनादेश देने का अधिकार है। अब प्रश्न है नागरिक कौन है नागरिकता का प्रश्न भारत के विभाजन के साथ ही सामने आया। जो लोग अपनी इच्छा से भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता मूलतरू खत्म हो जानी चाहिए थी जैसा कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनके साथ हुआ था और नागरिकता समाप्त होने के साथ ही उन भारतीयों की संपत्ति जो पाकिस्तान में थी बिना कोई मुआवजा दिये जब्त कर ली गई। भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक ढीलेपन के कारण जो लोग यहां से पाकिस्तान गए उन्हें वहां पर नागरिकता के साथ साथ उन्हें सस्ते दामों में जमीन जायदाद मिल गई और उनकी जायदाद जो भारत में थी उन्हें दुश्मन की जायदाद बता दिया गया पर उस संपत्ति को आने वाले भारतीयों को न ही दिया गया और न सरकार ने उस पर कब्जा किया। समय बीतने के साथ और भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने के उपरान्त पाकिस्तान गए हुए हर एक परिवार से कम से कम एक सदस्य जिनकी संपत्ति उस समय भारत में थी यहां लौट आए और पुनरू उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह से एक ही परिवार की दो मुल्कों में संपत्ति हो गई बिना अप्रवासी भारतीय नियम लागू हुए। जो भारतीय पाकिस्तान से आए उन्हें यहां रिफ्यूजी करार दिया गया और क्यूंकि उन्हें रातों रात पूर्वी पंजाब और पूर्वी बंगाल से खाली हाथ आना पड़ा था इससे उनकी हालत भिखारियों से बदत्तर हो गई थी। इसका एक ज्वलंत उदाहरण हाल ही में देखा गया जब कश्मीरी मूल पण्डितों को रातों रात श्रीनगर छोड़ना पड़ा और आज विस्थापित स्थिति में वे दिल्ली एवं उसके आस पास के क्षेत्रों में पड़े हुए हैं। ऐसी उक्त परिस्थिति में भारतीय नागरिक की परिभाषा बदलनी चाहिए थी जो भारतीय प्रजातंत्र में वोट बैंक के चलते नही बदली गई। भारतीय अनियंत्रित सीमा क्षेत्र क्यूं नही नियंत्रित किए गए इसका कारण राजनेता ही बता सकते हैं पर जो भी कारण हो यह देशहित में नही है पर इसके चलते अस्थिर जनसंख्या अर्थात सीमा पार निवासी बिना किसी बाधा या रूकावट के हमारे देश में केवल घुसपैठ ही नही वरन् गैरकानूनी हथियारों का कारोबार भी करते हैं और जघन्य अपराधों को अंजाम देने के बाद वापस पलायन कर जाते है जो हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था के परे है। यदि देशहित में उचित विवेचना की जाए तो आज के आतंकवाद का विकराल रूप उक्त कारणों से है।यह सत्य है वह परिवार जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे और उनके जो सदस्य भारत में देशप्रेम में नही वरन अपने स्वार्थ हेतु आए छरू दशक में उन्होंने अपना परिवार बढ़ा लिया और सबको भारत की नागरिकता के हकदार बना दिया और इसके विपरीत जो रिफ्यूजी यहां आए उनकी भारतीयता लम्बे समय तक असमंजस में पड़ी रही और आर्थिक विषमता इससे जुड़ी एक अहम समस्या थी जो अभी तक बनी हुई है। भारत में जन्में लोग कानूनन भारतीय बन जाते हैं और उचित समय आने पर वो अपना जनादेश दे सकते हैं। भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं और उनकी नागरिकता भारत में बनी हुई है उन्हें भी जनादेश का अधिकार है। जनादेश का अधिकार जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में भी है जहां के लोग गत छरू दशकों से सरकारी सिब्सडी का आनंद ले रहे हैं और भारत के हित में कोई भी कार्य करने में उनका रवैय्या हमेशा ढीला ही रहता है। उनकी सुरक्षा के लिए देश के कितने ही सुरक्षा कर्मियों ने अपनी आहुती दी पर फिर भी आज वो आजाद कश्मीर की रट लगाए हुए हैं।संघीय व्यवस्था को मानते हुए वोटर लिस्ट बनाना राज्य क्षेत्र के अधिकार में आता है और इसके लिए अलग विभाग की व्यवस्था है पहले यह विभाग अस्थाई था, चुनाव के दौरान यह क्रियाशील हो जाता था। अब यह विभाग स्थाई रूप से कार्यरत है क्यूंकि पहले चुनावों का मध्यांतर राज्य या केन्द्र में पांच वष का होता था पर आज के दल–बदल के परिवेश में आज ये कहना मुश्किल है कि कौन सी सरकार कितने दिन चलेगी। यहां यह कहना अनुचित न होगा कि बड़े स्तर पर रूपये का आदान प्रदान भी इसका एक बड़ा कारण है। इतनी बड़ी जनसंख्या जो जनादेश देती है उसकी सही तौर पर जांच–पड़ताल नही की जाती है, ऐसा देखने में आया है जो नागरिक और उनके पारिवारिक सदस्य सालों से एक ही स्थान पर रहते है उनका नाम वोटर लिस्ट में नही रहता है और होता भी है तो बदला हुआ होता है जबकि उसी क्षेत्र में अस्थाई रूप से रहने वाले या काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में मुस्तैदी से दर्ज किया जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था नही है कि कोई अधिकारी स्वयं जाकर बनाई गई सूची की अपने स्तर पर दोबारा जांच करे। दुभार्ग्य से चुनाव आयोग उम्मीदवारों के आचार संहिता की बात तो करता है पर मतदाता सूची की खामियों पर चुप्पी साध लेता है जो प्रजातंत्र का मूल है। यह भी देखने में आया है कि राजकीय सरकारी तंत्र मतदाता सूची को अपने अनुसार प्रभावित करता है। ऐसी भी कोई व्यवस्था नही है कि यदि किसी वास्तविक वोटर का नाम विभागीय कारणों से मतदाता सूची में मौजूद न हो और नियत दिन पर वह मतदान न कर सके तो उसका अमूल्य वोट बाद में प्राप्त हो सके ऐसा कोई प्राविधान नही है। भारतीय जनतंत्र प्रत्यक्ष नही है जैसा कि स्विटजरलैण्ड का प्रजातंत्र है, यहां उम्मीदवार की विजय के पश्चात् उसके नेतृत्व क्षमता की खामियां उजागर होने पर चयनित उम्मीदवार को पुनरू मतदान कर वापस बुलाने का प्राविधान नही है, जिस विभाग को मुख्य चुनाव मतदाताओं की ही पूर्ण जानकारी न हो वे चुनाव ही निष्पक्ष निबटा दें यही बहुत है, भारी जनसंख्या वाले इस देश में पुर्नमतदान की तो वे कल्पना भी नही कर सकते। अन्य शब्दों में मतदाता सूची बनाने वाला विभाग और चुनाव आयोग मतदाता सूची की प्रामाणिकता को महत्व नही देते जो आज की स्थिति में बेहद चिन्ताजनक है, इसी के चलते आज देश के राज्य और केन्द्र के प्रतिनिधियों में बाहुबली, माफिया और समाज के निकृष्ट लोागों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि सदन में असंसदीय भाषा का खुलेआम प्रयोग हो रहा है और सदन का अध्यक्ष उसे रोकने में नाकाम रहता है केवल संसदीय ब्यौरे से इन अशोभनीय शब्दों को हटाने की बात कह देता है। इसी पृष्ठभूमि के चलते चुनाव में बूथ पर कब्जा व राष्ट्रनेताओं का अपने प्रतिद्विन्दयों पर पर सार्वजनिक रूप से अशब्दों का प्रयोग करना जैसे हाल ही में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादव ने वर्तमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार के बारे में कहा या लालू प्रसाद यादव ने वरूण गांधी व सुषमा स्वराज पर फिब्तयां कसीं। आज के प्रजातंत्र में गठबन्धन एक ऐसी बीमारी है जो अपने स्वार्थहित के लिए की जाती है, कल का दुश्मन आज का दोस्त और आज का दोस्त कल दुश्मन बन जाता है जैसे उत्तर प्रदेश की बहन जी एक समय बाहुबली मुख्तार अंसारी की जानी दुश्मन थी दोनों अब दोनो दोस्त बन चुके हैं, हमारे पत्रकारों द्वारा पूछने पर मुख्तार अंसारी की बहन जी के प्रति समर्पित भावना कहती है कि मायावती को ही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। देश की बागडोर ऐसे ही घटिया और मक्कार बाहुबली माफियाओं के हाथ में खिसकती जा रही है। इसका प्रमाण समय समय पर आम जनता को मीडिया के जरिए मिलता रहता है कि जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रगान के रचयिता का नाम नही पता होता, संवैधानिक नीतियों की जानकारी नही होती और तो और बजट पेश करने के समय सदन में उपस्थित नही होते क्यूंकि उन्हें कुछ आता ही नही और सदन की मर्यादा का कोई ज्ञान भी नही होता। पाकिस्तान, इटली की ये अवस्था है जहां तीन चौथाई जनप्रतिनिधी बाहुबली और माफिया है और आम जनता से उन्हें कोई विशेष सरोकार नही है अतरू ये आवश्यक है कि चुनाव आयोग इन मामलों को गंभीरतापूर्वक ले और इस प्रक्रिया में बाधा बनने वाले लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करे। आज तो विज्ञान का जमाना है मतदान के बाद जो निशान लगाए जाते हैं उसे हटाया जा सकता है और ऐसा भी देखने में आया है कि एक व्यक्ति दस वोट डालने में समर्थ है हम इसी से प्रजातंत्र का अंजाम समझ सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ऊपर बताई गई खामियों से अवगत हैं, स्थान अनुसार और समयानुसार उसका उपयोग कर लेते हैं, इसी कारण से चुनावों के दौरान हिंसा की बहुत सी घटनाएं सुनने में आती हैं जिसके चलते जान–माल की भारी हानि भी होती है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के द्वारा उम्मीदवारों के व्यक्तिगत या पार्टी से जुड़े

शेष पृष्ठ 6 पर...

पाकिस्तान में उर्दू में घुलती जा रही है हिंदी

बाल मुकुन्द

यह जानकर आपको शायद आश्चर्य हो कि पाकिस्तान की उर्दू में हिंदी बहुत तेजी से घुलती जा रही है। वहां आज की आम बोलचाल में आप सुन सकते हैं कि मेरा विश्वास कीजिए, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है वगैरह। भारत के ज्यादातर पड़ोसी देशों में हिंदी बोली और समझी जाती है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे देशों में शामिल हैं। श्रीलंका में सिर्फ सिंहली और तमिल बोली जाती है, लेकिन वहां हिंदी फिल्में खूब शौक से देखी जाती हैं। जाहिर है, लोग थोड़ा–बहुत समझते भी होंगे। जो लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदी धीरे–धीरे खत्म हो रही है, वे इसके बढ़ते हुए दायरे को नहीं देख पा रहे हैं। इसका दायरा गैर हिंदी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। बहुभाषी संवाद की भाषा 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 1.21 अरब है। इनमें से 41.03 प्रतिशत लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा बताते हैं। यह संख्या मोटे तौर पर हिंदी प्रदेशों की आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे देश में लगभग 40 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। इनमें से 40 प्रतिशत रेलवे में, 16 प्रतिशत सूचना–संचार में, 15 प्रतिशत डिफेंस में और 4.5 प्रतिशत फाइनैंस में हैं। इनमें से ज्यादातर कर्मचारियों को एक से दूसरे भाषाई क्षेत्रों में जाना पड़ता है। तब हिंदी ही उनके काम आती है। अनेक क्षेत्रों से आए हुए अपने सहयोगियों से बातचीत करने के लिए वे आमतौर पर हिंदी का ही सहारा लेते हैं। इसके अलावा रोजगार की तलाश में जिस तरह से आबादी का पलायन हुआ है, उसने आपसी संवाद के लिए हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाया है। बेंगलुरू, चेन्नै या गुवाहाटी से दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या

अहमदाबाद में आया हुआ कोई आईटी इंजीनियर सिर्फ अंग्रेजी के सहारे अपना काम नहीं चला सकता। लेकिन यदि उसे हिंदी आती हो तो वह अहमदाबाद में गुजराती, चंडीगढ़ में पंजाबी, मुंबई में मराठी और कोलकाता में बंगाली जाने बिना भी अपना काम चल सकता है।

भाषाई जनगणना के समय हर नागरिक दावा करता है कि उसकी मातृभाषा अलग है। वह उर्दू, पंजाबी, तमिल, मैथिल, गोंडी, सिंधी या बंगाली जैसी कोई भी अनुसूचित भाषा हो सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति ने यदि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है या किसी बड़े संगठन में नौकरी करने लगा है या अपने भाषाई क्षेत्र से बाहर निकल आया है, तो इस बात की काफी संभावना है कि वह अपनी मातृभाषा छोड़ रहा है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, जो मिथिला के होकर भी मैथिली या कश्मीर के होकर भी कश्मीरी या डोगरी नहीं बोलते। इस भाषा का प्रयोग वे सिर्फ अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच करते हैं। बाकी समाज से संवाद स्थापित करने के लिए वे अंग्रेजी या हिंदी का सहारा लेते हैं। हिंदी इसमें अंग्रेजी से कहीं आगे है। वह सही मायनों में लिंक लैंग्वेज बन रही है– सबको जोड़ने वाली, इस बहुसांस्कृतिक देश की विकासमान लोकभाषा। विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं पर काम करने वाली एक संस्था इथॉनोलॉग के सर्वे के मुताबिक भारत में अंग्रेजी को अपनी सेकंड लैंग्वेज बताने वालों की तादाद आज भी 14–15 प्रतिशत सेज्यादा नहीं है। हिंदी के अलावा अन्य किसी भी भाषा को अपनी मातृभाषा बताने वालों की संख्या यहां 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। क्षेत्रीय भाषा बोलने वालों की तादाद तेजी से घट रही है और उनकी जगह धीरे–धीरे हिंदी लेती जा रही है।

असल में हिंदी को लेकर हमारा कंफ्यूजन कुछ पुरानी मान्यताओं के कारण है। आजादी के बाद यहां हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इसका अर्थ लोगों ने यह समझा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी भारतवासी हिंदी बोलेंगे और समझेंगे। कार्यालयों का सारा कामकाज हिंदी में होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार्यालयों में कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही बनी रही। वहां अंग्रेजी के बदले हिंदी लाने को ही हमने हिंदी के विकास का पैमाना बना लिया। इस जिद की वजह से जमीन पर पसरती हिंदी की ताकत को हमने देखा ही नहीं। अंग्रेजी हमें प्रभुत्वशाली इसलिए लगती है, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी ज्यादा है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनका कुल अंग्रेजी ज्ञान सौ–दो सौ शब्दों से ज्यादा नहीं है। लेकिन वे जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम पर उसका प्रभाव होता है। हम मान लेते हैं कि अंग्रेजी तेजी से बढ़ी आ रही है और हिंदी नष्ट हो रही है। पर यह समझना जरूरी है कि अंग्रेजी में अपना दफ्तरी काम निबटाना और जगहों पर अंग्रेजी बोलना–बतियाना दो अलग–अलग चीजें हैं। कोई क्लर्क अपनी ड्राफ्टिंग अंग्रेजी में ही करता है, क्योंकि यह उसकी मजबूरी है। लेकिन केंद्र सरकार के सेक्रेटरी स्तर तक के ज्यादातर अधिकारी सामाजिक मेलजोल में हिंदी को ही प्राथमिकता देते नजर आते हैं। कुछ हिंदी प्रेमी तर्क देते हैं कि हम अपनी शिक्षा–दीक्षा और सरकारी काम हिंदी में क्यों नहीं कर सकते? हमें अंग्रेजी की क्या जरूरत है? फ्रांस को देखो, इस्राइल और स्पेन को देखो–आखिर उन्होंने कैसे किया? दुर्भाग्य से ऐसे लोग नई और सही जानकारी नहीं रखते। 2012 की यूरोबैरोमीटर रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में आज 39 प्रतिशत लोग अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं और स्पेन में 22 प्रतिशत। इस्राइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है, लेकिन वहां की 85 प्रतिशत आबादी अंग्रेजी ही बोलती है। भारत में तो आज भी अंग्रेजी बोलने वाले 15 प्रतिशत से कम ही है।

हिंग्लिश-चिंग्लिंश

असल में हताश होने वाले लोग वे हैं, जो हिंदी के एक खास रूप को ही हिंदी मानते हैं। उसके रूप में होने वाले बदलाव और कई तरह की हिंदियों का पैदा होना वे स्वीकार नहीं कर पाते। अंग्रेजी वाले हिंग्लिश और चिंग्लिश को इंग्लिश का विस्तार मानते हैं। लेकिन हिंदी के विद्वानों के लिए किसी तमिल या बंगाली का हिंदी बोलना मजाक का विषय है। उन्हें हिंदी के विभिन्न रूपों में इसका विस्तार नजर नहीं आता। वे सिर्फ रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद और कामता प्रसाद गुरु की बताई हिंदी को ही हिंदी मानते हैं। इसीलिए उन्हें हिंदी संकटग्रस्त नजर आती है। लेकिन इस भारतीय उपमहाद्वीप में इसका विस्तार अंग्रेजी से कहीं ज्यादा तेज गति से हो रहा है।

कसाब के बाद अफजल पर निगाहें

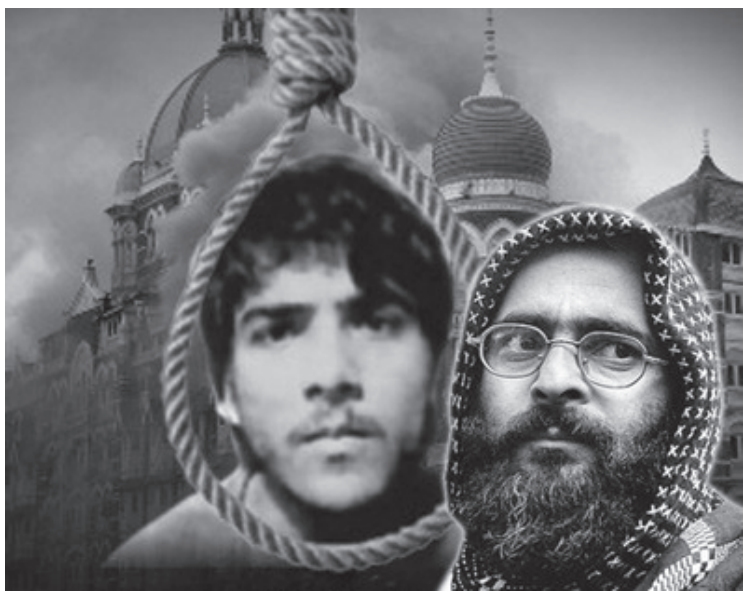

26 नवम्बर 2008 का दिन भारत के लिये दुर्भाग्यशाली था। ठीक उसी प्रकार 21 नवम्बर 2012 का दिन आतंकवादी कसाब के लिये भी वह दुर्दिन का दिन साबित हुआ कि स्वयं उसको अपनी मौत के लिये हस्ताक्षर करना पड़ा। कसाब जिस प्रकार कानूनी प्रक्रिया से गुजरा। गृह मंत्रालय ने जिस प्रकार सराहनीय भूमिका निभायी वहीं खुफिया विभाग की तारीफ होना भी गलत नहीं कि सारा मिशन बड़े ही वैधानिक ढंग से हुआ। कसाब की फांसी उन आतंकवादियों के लिये संदेश भी है कि भारत आतंकवाद को ही नहीं खत्म करना चाहता बल्कि आतंकवादियों का भी खात्मा करना चाहता है। जिसका वैधानिक प्रमाण है आतंकवादी कसाब को फांसी दिया जाना। यह इंसाफ था। जिसने गलत को गलत करार किया। इससे कानून की ताकत का भी आतंकवादियों को अहसास होगा।

मुंबई हमले के आरोपी अजमल कसाब को बुधवार को फांसी दे दी गई। सरकार ने इसका फैसला संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले किया। राजनीति में फैसले के समय की बड़ी अहमियत होती है। जाहिर है कि इतना बड़ा फैसला सरकार ने बहुत सी बातों को ध्यान में रखकर ही किया होगा। दया याचिका रद होने से लेकर फांसी देने तक सारी प्रक्रिया को गोपनीय रखा गया। सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से यह उचित कदम था। क्या कसाब को फांसी देने का फैसला करते समय सरकार के मन में मौजूदा राजनीतिक हालात का ध्यान नहीं रहा होगा। सरकार जिस तरह के संकटों से घिरी है उससे निकलने का कोई भी रास्ता उसके लिए मौजूदा हालात से राहत दिलाने वाला होगा। यह हालात का ही असर है कि आर्थिक मोर्चे पर उसके सही कदमों को भी संदेह की नजर से देखा जा रहा है। सरकार ने कसाब की दया याचिका नामंजूर करने का फैसला ऐसे समय लिया जब गुजरात में चुनाव अभियान चल रहा है और संसद में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर वह घिरी हुई है। अविश्वास प्रस्ताव का खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है। उसके समर्थक अपने पत्तो खोलने को तैयार नहीं हैं। राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो केंद्र सरकार का समर्थन करने वाले दल द्रमुक, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी गठबंधन के बीच खड़े हैं। ये तीनों दल खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर सरकार की नीति का विरोध करके एक कदम विपक्षी पाले की ओर बढ़ा चुके हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि ये तीनों दल सरकार गिराने की हद तक विपक्ष की ओर नहीं जाएंगे। विपक्ष की आस इन्हीं के समर्थन पर टिकी है।

मुंबई हमले को चार साल होने वाले हैं। 26 नवंबर, 2008 को महाराष्ट्र पुलिस के बहादुर सिपाही तुकाराम ओंबले ने कसाब को न पकड़ा होता तो? कसाब के अलावा हमारे पास क्या है? चार साल में भारत सरकार हमले की साजिश में शामिल लोगों की आवाज का नमूना भी हासिल नहीं कर पाई है। उन्हें भारत लाना और सजा दिलाना तो दूर की बात है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार आज भी पाकिस्तान में आराम से रह रहे हैं और हम जो हो गया उसे भूल जाने की बात करते हैं। कसाब को फांसी हो गई। अब मुंबई हमले को भूलकर आगे बढ़ने की वकालत करने वालों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। चंद दिनों पहले तक मुंबई हमले पर पाकिस्तान पर कोई दबाव डालने में नाकाम रहने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पाकिस्तान यात्रा की तैयारी हो रही थी। जो बात पाकिस्तान कहता था वही अब हमारे नेता और मंत्री कहने लगे हैं कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है–बिना इस बात का विचार किए कि दोनों के हालात में जमीन–आसमान का फर्क है। हम जिस आतंकवाद को झेल रहे हैं वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ और उसकी सेना की उपज है। हमारे प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके, शर्म अल शेख में उन्होंने पाकिस्तान के इस आरोप को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया कि बलूचिस्तान में हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान से संबंध बेहतर हों, इससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता, पर सवाल है कि किस कीमत पर। क्या देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान की कीमत पर? केंद्र की संप्रग सरकार पाकिस्तान समर्थित और पोषित आतंकवाद के मुद्दे पर दबाव बनाने की कोशिश करने के बजाय आतंकवाद का घरेलू राजनीति में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान और आतंकवाद पर एक सीमा से ज्यादा बोलने पर आप मुस्लिम विरोधी मान लिए जाएंगे। कसाब को फांसी इसलिए नहीं दी गई कि वह आतंकवादी था। क्या वह पाकिस्तानी नागरिक न होता तो भी उसकी दया याचिका पर इतनी ही जल्दी फैसला होता? आतंकवाद ही आधार होता तो अफजल की दया याचिका पर छह साल से फैसला रुका नहीं रहता। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अफजल को फांसी हुई तो कश्मीर घाटी जल उठेगी। ऐसा कहने और मानने वाले तो जाने–अनजाने यही संदेश देते हैं कि मुसलमान आतंकवादियों से सहानुभूति रखते हैं। इस देश के मुसलमानों के साथ इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता।

ईसा मसीह का जन्म (क्रिस्मस)

बैसिल जोसेफ

आज से लगभग दो हजार साल पहले पस्चिम एशिया के यरुस्लेम नगर में एक छोटे से कस्बे बेतलेहम में ईसा नाम के बालक का जन्म हुआ जो दुनिया में ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। उनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ था जो नासरत में रहा करते थे। नासरत जो जॉर्डन में स्थित है। इस समय यरुस्लेम पर रोम का अधिकार था। रोमन राजा हेरोद यहूदियो के इस देश में राज करता था। वह स्वाभाव से क्रूर, और निर्दयी प्रवृत्ति का था। यरुस्लेम में रहने वाले यहूदी बड़े अंधविश्वासी थे। रोम वासी इन पर अत्याचार करते थे। एक बार लोगो ने राजा हेरोद को जाकर यहूदियो के भावी राजा के जन्म की बात कही, इस खबर को सुनकर राजा हेरोद विचलित हो उठा और उसने अपने सैनिकों को बालक येशू को मार डालने के आदेश दिए। इस बात का पता जब बालक येशू के पिता को पता चला तो वे रातों रात उस गाँव को छोड़कर अपने बेटे की रक्षा के लिए मिस्र देश चले गये। जब राजा हेरोद को बालक येशू नही मिले तो उसने २ वर्ष तक के सभी बच्चों का कत्ल करवा डाला, लेकिन उसका कोई भी फल उसे नहीं मिला। रोमन राजा हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु येशू के माता पिता उन्हे लेकर वापस आए।

वे लोगों को बुराई से बचाएँगे,उन्हे पाप के सागर से निकालेंगे, गरीबों व रोगियों की तन मन से सेवा करेंगे और जब वे 31 वर्ष की आयु के थे तो उन्हें ईश्वरी प्रेरणा मिली जिसे पाकर उन्होने तपस्या की। और हम जानते हैं की तपस्वियों के तप को भंग करने के लिए शैतान चारों ओर घूमते रहते हैं, इसी तरह शैतान ने उन्हें मार्ग से हटा कर उनकी तपस्या को भंग करने की पूरी पूरी कोशिश की लेकिन प्रभु येशू को अपने वश में ना कर सका। येशू ने आपसी भेद भाव मिटाने के लिए कहा और सबको एकता के बंधन में बाँधने के उपदेश दिए, अपने को ईश्वर का पुत्र कहा और लोगो को पुजारियों के बहकावे में आने से रोका उनका यश चारों ओर फैलने लगा वे ईसा मसीह कहलाने लगे जिसका अर्थ है मुर्दों को जिलाने वाला।

वक्त बीतता गया और उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गयी और उनके उपदेश सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते, हजारों की संख्या में लोगो को देखकर उन्होने एक ऊँचे टीले पर खड़े होकर उपदेश देना शुरू कियाद्य जब जब किसी का उत्कर्ष होता है तब तब उसके दुश्मनों का दायरा बढ़ने लगता है। जब ईसा मसीह ने पुजारियों के आडंबर का भांडाफोड़ किया तो उन्होने रोम के राजा से शिकायत की ईसा मसीह रोम के विरुध लोगो को भड़का कर रोम का राज्य समाप्त करना चाहता है तो राजा ने उन्हे गिरफ्तार करने का फरमान जारी किया। पहले तो ईसा मसीह इससे बचते रहे किंतु एक दिन उनके एक शिष्य ने उनके साथ विश्वासघात किया और वो पकड़ लिए गये। उन पर मुकदमा चलाया गया और सूली पर चढ़ाने के आदेश दिए गये।

उन पर मुकध्दमा चलाया गया और सूली पर चढ़ाने के आदेश दिए गये। उन्हें कल्वारी नामक पहाड़ तक कोढों से मारते हुए ले जया गया उनके कपड़े तक फट गये और उनके सर पर काँटों का ताज पहनाया गया उनका शरीर लाहुलुहान हो गया और फिर उन्हे क्रूस पर लेटा कर उनके हाथ और पाँव में कीलें ठोकी गयी और उन्हे क्रूस पर लटकाया गया। प्राण त्यागने तक वे ईश्वर से प्रार्थना करते रहे हे पिता, इन्हे क्षमा करना, क्योकि ये नहीं जानते की ये क्या कर रहें हैं।

ईसा मसीह ने सूली पर अपने प्राण त्याग दिए और मृत्यु के 3 दिन बाद जीवित हुए और उपदेश दिए इन उपदेशों का इतना प्रभाव रोम के सम्राट पर पड़ा की उसने इसे राज्य धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। ईसा मसीह ने हर गम, हर दुख, हर कष्ट हंस कर सहा और अपने विरोधियो और दुश्मनों को क्षमा किया हर जुल्म को खुशी से स्वीकार करते हुए खुदा के बेटे ने दुनिया को बता दिया क्षमादान किसे कहते हैं। ईसा मसीह के नाम का यश कभी नही घटेगा वह कल था, आज है, और सदा रहेगा।

वोट के लिये तरह-तरह के हथकण्डे

मनमोहन सिंह की सरकार ने आर्थिक सुधारों के नाम पर विपक्ष का कोई भी दबाव नहीं माना। सरकार खुद ही दांव पर लग गयी थी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर यूपीए–2 सरकार का साथ छोड़ दिया। इस खतरे को उठाते हुए भी कांग्रेस ने वोट के लिये एक दूसरा रास्ता भी खोजा है। इसको सब्सिडी का सीधे भुगतान नाम दिया गया है। सरकार का मानना है कि जिस पात्र को साब्सिडी दी जा रही है, वह उसे नहीं मिल पाती जबकि सरकार के खजाने से रकम निकल जाती है। यह बात अभी आम जनता को समझ में नहीं आ रही है। इसका एक कारण यह कि सरकारी योजनाओं का आधा–अधूरा लागू होना है लेकिन जैसा सरकार दावा कर रही है कैश ट्रांसफर योजना साल भर में पूरे देश में लागू हो जाएगी तो इसका प्रभाव भी मनरेगा जैसी योजना से कम नहीं होगा।

संसद के आम चुनाव नजदीक आ गये तो कांग्रेस को 2009 में किये गये जनता से वादे याद आये। आर्थिक सुधारों के नाम पर पेट्रोल उत्पादों पर सब्सिडी खत्म करने के कड़वे फैसले लेने वाली यूपीए–2 सरकार ने जनता को खुश करने का भी रास्ता खोजा है। उसका इरादा है कि गरीबों को रियायती दर पर जो चीज मिल रही थी, वह मिलनी चाहिए लेकिन उसमें कोई बिचौलिया हाथ न मारे, इसलिए उसका स्वास्थ्य बदला जा रहा है। मसलन अभी तक सस्ता मिट्टी का तेल गरीबों को मिलता था। यह तेल कोटेदार स्वयं पाता। अक्सर समाचार मिलता है कि राशन का गेहूं बाजार में बिकते देखा गया। कालाबाजारी का मिट्टी का तेल पकड़ा गया। इस प्रकार गरीब के हत्थे सरकारी मदद बहुत कम लगती थी।

इसी मदद को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है मनमोहन सिंह की सरकार और उसको नाम दिया है 'आपका पैसा, आपके हाथ' अर्थात् सब्सिडी की रकम सीधे आपके हाथ में दी जाएगी। पहले यह कहा गया था कि लाभार्थी के बैंक खाते में सब्सिडी की रकम जमा की जाएगी। यह भी इसलिए किया जा रहा था कि कहीं बिचौलियो सब्सिडी न हजम कर जाएं लेकिन उसमें उन गरीबों को दिक्कत हो सकती थी जो बैंक में खाता खुलवाने के लिये भी समर्थ नहीं हैं। सरकार का नये साल में यह देश को तोहफा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार पहली जनवरी से देश के 16 राज्यों में सीमित शहरों में पहले इसे लागू किया जाएगा। ध्यान रहे कि मनरेगा को भी पहले कुछ राज्यों के चुनिंदा जिलों तक ही सीमित रखा गया था लेकिन राहुल गांधी की मांग पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसे देश भर में लागू कर दिया और यूपीए–2 सरकार बनने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मनमोहन सिंह की सरकार ने 31 दिसम्बर 2013 अर्थात् चुनावी वर्ष 2014 के पूर्व ही इस योजना को पूरे देश में लागू करने की बात कही है। अभी इस योजना के बारे में गांव तो दूर शहरों के लोग ही नहीं जानते। सच्चाई तो यह है कि तमाम योजनाओं की जानकारी आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती जबकि सरकारी अमला इसीलिए मोटी–मोटी रकम पाता है और स्वयंसेवी संस्थाएं 'जन जाग सकता' का अभियान चलाती रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कितने किसानों को यह मालूम है कि यदि वह भिण्डी या कद्दू की फसल में कोई खोज करता है तो उसे एक लाख तक का पुरस्कार मिलेगा। मलिहाबाद में पट्टी के एक बागवान कलीमुल्ला खान आम के पेड़ में इस तरह के प्रयोग करके पैसे के साथ कीर्ति भी कमायी है। बहरहाल, इस मामले में ज्यादा चर्चा फिर करेंगे। अभी सरकार की योजना 'आपका पैसा आपके हाथ' की बात चल रही है। कांग्रेस चाहती है कि किसानों की कर्ज माफी, मनरेगा और आरटीआई (सूचना का अधिकार) जैसी योजनाओं की तरह है इसका भी पूरा राजनीतिक लाभ लिया जाए। पार्टी ने अपने संगठनात्मक स्तर पर इसकी तैयारी कर ली है। शीघ्र ही कांग्रेस जिलाध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया जायेगा क्योंकि अभी इसे 51 शहरों में ही लागू किया जा रहा है। पी. चिदम्बरम के अनुसार 'आपका पैसा आपके हाथ' योजना में 42 कार्यक्रम शामिल किये जायेंगे। पहली जनवरी से पेंशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा और आंगनबाड़ी समेत 29 योजनाओं का पैसा पात्रों तक सीधे पहुंचा दिया जाएगा। सरकार कुछ दिन इसकी कार्यप्रणाली देखेगी और शीघ्र ही एलपीजी में सब्सिडी समेत बाकी योजनाओं को भी इसमें शामिल कर लिया जायेगा।

पृष्ठ 4 का शेष

भारत में अनूठा...

बेतहाशा चुनावी खर्चे की बात तो कही है पर इस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नही लगा पाई। आज भी पैसे, शराब, कपड़े और कम्बल आदि बांटे जाने की खबरें मीडिया के द्वारा लगातार मिल रही हैं। खर्चे का इतना लम्बा चौड़ा ब्यौरा देखकर और साधारण जनता, जिसमें अनपढ़ और पिछड़ा वर्ग भी शामिल है उनका पैसे के प्रति लोभ और व्यक्तिगत स्वार्थ को देखकर आज कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात सोच भी नही सकता। ऐसा भी देखने में आया है कि कई उम्मीदवार नांमाकन तो करते हैं पर पार्टी से पैसा मिलने के बाद ठीक चुनाव के मुहाने पर अपना नाम वापस ले लेते हैं। संविधान रचयिताओं ने संभवतरू इस पर कोई विचार नही किया होगा और चुनाव आयोग भी इस पर रोक लगाने में असमर्थ मालूम होता है।भारत की स्वतंत्रता के साथ जो नामचीन राजनीतिक पार्टियां सामने आईं उनमें कांग्रेस,जनसंघ और कम्यूनिस्ट पार्टी शामिल थी समय बीतने के साथ इन पार्टियों के चुनावी घोषणापत्रों में आमूल परिवर्तन होते रहे। कांग्रेस पार्टी जिसने देश की स्वतंत्रता में मुख्य भूमिका निभाई उसका चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी से बदलकर हाथ के पन्जे तक सीमित हो गया हांलाकि महात्मा गांधी ने अपना दूरदर्शिता के कारण यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस पार्टी का विघटन कर दिया जाए क्यूंकि चुनाव हथकण्डों में आदशों की बलि चढ़ जाएगी और भारतीय जनसंघ जिसकी लौ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान देकर भी जलाए रखा ने अपने उसे अटल बिहारी एण्ड कम्पनी ने अपने मूल्यों से समझौता कर भारतीय जनता पार्टी में बदल दिया, सोशलिस्ट पार्टी तो जैसे अपना वजूद ही खो बैठी और किसके साथ गठबन्धन करे इसी पशोपेश में पड़ी रही और आम जनता का विश्वास खो बैठी, भारत की कम्यूनिस्ट पार्टीयां तो जैसे तय ही नही कर पाई कि उन्हें चीन का साथ देना चाहिए या रूस का?और उधेड़बुन में तरह तरह के राजनैतिक पैंतरे बदलती रही। इस बीच छोटी छोटी पार्टियां व निर्दलीय उम्मीदवार अपने स्वार्थपूर्ति हेतु कुकुरमुत्तों की तरह उगते रहे पर राष्ट्र की उिन्नत में उनका योगदान शून्य रहा। छठे दशक की शुरूआत से पहले ही केन्द्र में एक अकेली पार्टी की सरकार का गठन होना संभव नही रहा और सरकार गठन के लिए के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टियों का सहारा लेना पड़ा, यह स्वयं में एक बहुत कठिन कार्य है क्यूंकि इस प्रकार के संगठित राजनीतिक दल देशहित की जगह पार्टी या व्यक्तिगत स्वार्थों पर अधिक बल देते हैं। ऐसी स्थिति में सभी पार्टियां अपने प्रतिनिधी उन सभी जगहों पर तैनात करवा देते हैं जहां से आय का स्त्रोत हो। इस प्रकार के धन की आवश्यकता राजनीतिक प्रतिनिधियों की खरीद–फरोख्त के लिए होती है। चुनाव पूर्व गठबन्धन और चुनाव बाद के गठबन्धन यह भारतीय राजनीति में मिलीजुली सरकारों की देन है, इस प्रकार के गठबन्धनों में पार्टी हित सर्वोपरि होता है न कि देशहित और किसी तरह सरकार में शामिल होने का या सत्ता में आने का जोड़ तोड़ इन पार्टियों का मुख्य उद्देश्य होता है। भारतीय संविधान रचयिताओं ने इसकी कल्पना भी नही की होगी अन्यथा इस पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने निश्चय ही कोई नियम बनाया होता। एक और नई व्यवस्था भारतीय जनतंत्र में सामने आई कि राजनैतिक पार्टियों का सिंहासन एक ही परिवार के लोगों को एक के बाद एक मिलने की परंपरा बन गई भले ही वे उसके योग्य हों या न हों उदाहरण के तौर पर लालू–राबड़ी यादव व राबड़ी के परिवारवाले, मुलायम–अखिलेश सिंह यादव, विजयराजे–माधवराव–वसुन्धरा राजे–ज्योर्तिादित्य सिंधिया, करूणानिधी–स्टालिन, शेख–फारूख– उमर अब्दुल्ला, सोनिया–राहुल गांधी, सुनील–संजय दत्त, नवीन–बीजू पटनायक, बनारसी दास–अखिलेश दास, बाल–राज ठाकरे आदि। देश की राजनीति बहुत कुछ मुम्बई फिल्म इण्डस्ट्री की स्टारपुत्र/पुत्री प्रथा से मिलता जुलता है।राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए आसान रास्तों को अपनाया जो अनैतिक भी थे। संविधान में धर्मनिरपेक्षता हिदायती सिद्धान्तों में है पर इसे मूल अधिकारों में परिवर्तित कर दिया गया, चुनाव के समय जातिवाद धर्मवाद सभी का सहारा इतने खुले रूप में लिया गया कि भारतीय समाज गठित होने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया।धन के चलते अब भारतीय राजनीति में फिल्मी कलाकार, क्रिकेटर व बाहुबली ही मैदान में आ सकते हैं और देश का भविष्य अपने सीमित दायरों के अनुसार निहित करते हैं।चुनाव आयोग पहले तो निष्क्रय सा प्रतीत होता था पर टी.एन सेशन ने इसके महत्व और मजबूती को विशेष मानयता दिलाई, इसी के चलते आज चुनाव आयोग निर्भय होकर सभी राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाती है और काफी हद तक दलों को विवश भी कर देती है कि वे इसका पालन करें पर यदि राज्य सरकारें व केन्द्र सरकार उचित सहयोग न प्रदान करें तो आचार संहिता धरी की धरी रह जाती है। प्रजातंत्र एक समझदारी का गठबंधन है जो प्रत्येक देशवासी के हित में होना चाहिए ऐसे तंत्र में नाकारात्मक कार्यों की बहुत गुंजाईश है क्यूंकि इसमें खूद को अनुशासित करना बेहद आवश्यक है। जब यह अनुशासन अपने स्वार्थ हित के लिए ताक पर रख छोड़ा जाता है तभी विभिन्न प्रकार की विषमताओं का जन्म होता है। राजनेता का कर्तव्य जैसा आज परिलक्षित होता है केवल धन ही कमाना नही है वरन प्रजातंत्र की नींव को मजबूत करना भी है। दूसरे किसी तंत्र में ऐसा खुलापन और स्वतंत्रता नही है अतः यह आवश्यक है कि प्रजातंत्र की गरिमा को बनाए रखा जाए क्यूंकि खोखली नींव पर बुलन्द इमारतें नही खड़ी होती।

500 Girls have taken oath to eliminate child labour

❑ ***Rakesh Senger***

6th November, 2012, New Delhi : Five hundred students from Aditi Mahavidyala (Delhi University) pledged for a child labour free Diwali celebration this year. Mr. Kailash Satyarthi, founder of Bachpan Bachao Andolan inaugurated this year's Diwali celebration. He said that he envisioned a India as a child labour free country and exhorted the students extwend their for this dream.

Over 500 girls came together and taken oath, "we will never keep child labour and fight against employing child labourers." They celebrated this festival with diyas and also said that they will stay away from using crackers on Diwali instead will only use Diyas on this festival of lights and justice.

Satyarthi said, "there are 6 crore child labourers in our country, working in extremely hazardous condition and the main cause of poverty is to employing child labourers"

"Health Card for India"

Indo-German Dialogue on Social Policy

As part of a bilateral social dialogue, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), jointly with the Ministry of Labour and Employment, has invited experts from Germany and India to discuss the use of smart cards for electronic health (e-health) records.

Rashtriya Swasthya Bima Yojana, RSBY, the National Health Insurance for the poor has provided smart cards for about 33 Mio. Households (November 2012). Currently the smart card houses the biometric data to identify the members and the RSBY budget of the household.

On Wednesday, November 21st, the Deputy Chief of Mission and Head of Department for Economic and Global Affairs of the German Embassy in New Delhi, Cord Meier-Klodt, will inaugurate the three-day workshop.

Ahead of the workshop, Mr Meier-Klodt stated, "Germany and India share a broad common understanding of how markets should grow. We are used to call it Social Market Economy, Indians call it Inclusive Growth. The meaning is similar: No development for just a happy few. The introduction of smart cards to secure health care for millions and millions of Indians working in the informal sector (RSBY) is yet another example of this common understanding. The Workshop we are opening today will focus on areas where Germany and India can benefit from each other´s experience in e-health in order to further improve their policy for those most in need of assistance."

The workshop presents an opportunity for both countries to exchange ideas and experiences with regard to the topic e-Health and Personal Health Records. Among the speakers will be experts from the Ministry of Labour and Employment, the Ministry of Health and Family Welfare, the German Federal Ministry of Health, the German Medical Association, the German Hospital Federation as well as experts from German and Indian insurance companies and IT-experts.

The implementation of e-health and the application of smart cards for the creation of Personal Health Records have been identified as a priority area for policy learning and capacity strengthening in both countries. The shift from a paper based to an electronic format will increase efficiency and will enable a better privacy protection as well as pre-authorization of health transactions by storing the relevant information on the card.

In India, Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) has introduced such a smart card-based system. The smart card facilitates the exchange of information and is the key to run a paper- and cashless scheme. Since its launch, it has catered to the health and medical needs of approximately 4.2 million people (November 2012).

Similarly, a large-scale electronic health card project has started to be implemented in Germany which is yet in an early stage of implementation. In the future, however, it may also contain administrative data, supplemented by essential health and emergency, data which will then be of similar nature as the data on India's health insurance cards.

Through a direct exchange between policy makers, implementers and individual experts, the workshop shall facilitate the exchange of the different "lessons learnt" and ideas for a future e-Health application. It shall contribute to a better understanding of innovative solutions for e-Health and identify areas for cooperation to improve the implementation of health insurances in both countries.

फिर एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र ने लगाई खुद को फाँसी

चन्द्रकांत सिंह
छात्र, (ईम्मी)

17 नवम्बर 2012रू कुछ ही दिन पहले खबर थी की दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ने मुखर्जी नगर में 3 मंजिल की बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दी। अभी उस केस की फाइल बंद भी नहीं हुई थी कि फिर एक छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया। कल सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र ने खुद को फंसी लगा कर अपनी जान दे दी। दिल्ली के हिन्दू कॉलेज में पढने वाले शशि शेखर मिश्रा ने कल सुबह 5–6 बजे के बीच पंखे से लटक कर खुद को फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। शशि शेखर मिश्रा पटना बिहार से था और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज से ड। (हिंदी) प्रथम वर्ष की पढाई कर रहा था। कॉलेज के हॉस्टल के रूम नंबर 111 में वो अकेला रहता था। बताया गया की रात को 2 बजे तक उसके कुछ दोस्त उसके साथ ही रूम में थे। सुबह 9.30 बजे जब कॉलेज जाने का टाइम हुआ तो दोस्तों ने उसके रूम में जाके देखा तो रूम अन्दर से बंद था। रूम खुलने के बाद देखा तो शशि का शव पंखे से लटका हुआ था। तुरंत ही पुलिस को इत्तेला किया गया और 9. 45 तक पुलिस हॉस्टल पहुंची और अपनी कार्यवाही शुरू की। तुरंत शशि के घर पे भी जान करी दे दी गयी और शाम 4.30 बजे तक शशि के पिता दिल्ली पहुँच गए। शशि के साथ रहने वाले दोस्तों ने बताया की जब उन्होंने सुबह देखा तो शशि के रूम से एक अंतिम नोट भी मिला था जिसमे उसने एक कविता लिखी थी और यह पुष्टि की कि उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि वो खुद है।

शशि 21 वर्षीय युवक छात्र था जो पिछले कुछ सालों से अपने पढाई के चलते दिल्ली में ही रह रहा था। वह बिहार के पटना जिले से था पर पढाई के चलते अपने घर और परिवार से दूर दिल्ली में अपनी पढाई कर रहा था। परिवार में माता–पिता, भाई और एक बहन थी जो की पटना में ही रहते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज से ही उसने अपनी ग्रेजुएशन की। शशि दो बार दिल्ली विश्वविद्यालय का टोपर रह चुका है ठ। के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उसने 79ः हांसिल किये और दिल्ली विश्वविद्यालय का टोपर बना। ठ। की परीक्षा पास करने के बाद शशि ने जवाहर लाल नेहरा विश्वविद्यालय में भी प्रवेश परीक्षा दी और अच्छे अंको से पास भी की, लेकिन दाखिला नहीं करवाया और हिन्दू कॉलेज से ही ड। करने का निर्णय लिया। दोस्तों ने बताया की शशि बहुत ही सीध ाा सादा था और अधिकतर अकेले रहा करता था। वह अपनी ही जिंदगी में रहता था, किसी से कोई ज्यादा बात नहीं करता था। उसे बस अपनी जिंदगी से मतलब था। अपनी पढाई को लेकर हमेशा चिंतित रहता था पर पढने में बहुत अच्छा था। पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार तनावपूर्ण लग रहा था। शायद तनाव के कारण ही उसने आत्महत्या कर ली।

दिल्ली पुलिस सारी छानबीन कर रही है। मौरिस नगर पुलिस थाणे के सब–इंस्पेक्टर रोहित मामले की तहकीकात कर रहे हैं। शव को तुरंत पोस्ट मोर्टेम के लिए भेज दिया गया था। आज सुबह 10 बजे शव का हिन्दू राव हॉस्पिटल में पोस्ट–मोर्टेम किया गया। पोस्ट मोर्तेम रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं की गयी है। शाम को शव परिवार के हवाले कर दिया जायेगा। आज हिन्दू कॉलेज के ऑडिटोरियम में सारे कॉलेज ने शशि शेखर मिश्रा को श्रद्धांजलि थी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

फिन्स संगठन ने कि भारत–भूटान सीमा क्षेत्र का किया जायजा

❑ राजेश शर्मा

जयगांव। गैर सरकारी संगठन फिन्स संगठन के 17 सदहस्यों ने शुक्रवार एंव शनिवार को सुबह दस बजे से भारत एंव भूटान के सीमा क्षेत्र में चल रही तमाम समस्याओं को लेकर जायजा व निरक्षन किया। बताया जाता है इनफिन्स संगठन टोली भारत के पंजाब, केरला, महाराष्ट्र पश्चिम, दक्षिण बंगाल, एंव कासी क्षेत्र प्रान्तों से आया है । जो इस टोली ने राष्ट्रीय की सुरक्षा और इन तमाम सिमा क्षेत्र पर रह रहे उन तमाम भारतीय नागरीकों से हर तरह के सम्बंध को लेकर बातचीत एंव भारतीय नागरिक कों अपने बदन की सुरक्षा एंव जागरुकता जैसी तमाम विषय को लेकर जानकारी देते हुए कहा। जो इस फिन्स संगठन ने दो दिन में ६६ अंतराष्ट्रीय पिलर से ७६ अंतराष्ट्रीय पिलर का इस सीमा क्षेत्र भारत भूटान के पास के सीमा क्षेत्र के अंतराष्ट्रीय लगभग १८ किलो मीटर की दूरी पैदल यात्रा के तहत स्थानीय श्याम शुन्द्र शर्मा, गंगा शर्मा लिला धर राठी , परिमल देव शर्मा कृपा शंकर जयसवाल एंव राम बाबु बडरे के अगगुवाई में भ्रमन किया। इन आए टोली ने अंतराष्ट्रीय पिलर ६६ के पास वाले क्षेत्र के समसान काली मन्दिर भूटान ने उन के सीमा अधीन करने पर काफी दुःख की बात बताया तथा उन्होंने इस मामले को लेकर भारत सरकार के उच्च अधि ाकारी से दिल्ली मे बातचीत की जाने की जानकारी भी दी है । इस सम्बंध में पंजाब प्रान्त से आए बलवन्द सिंह एंव केरला से सुनील कुलकरनी ने बताया है आज के दिनों में राष्ट्रीय सुरक्ष एंव देश की प्राथमिक राष्ट्रीय के अनिवार्यता हो चुका है इस विषय को लेकर आज भारत के विभिन्न हर अंतराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में निरक्षन करने का कार्य हो रहा है जबकि पिछले दिनों भारत देश के काफी स्थान के जमीन खो चुका है, उदाहरण में उन्हें सन् १६४७ को भारत के कश्मीर पर पाक ने ८३,००० वर्ग किलो मीटर कब्जा किया है तथा इसी तरह से १६६० में भी वैरुवाडी पर पाक का कब्जा हुआ तथा १६६२ में चीन देश ने सियाचीन, कैलास मानसरोवर एंव पूर्व उत्तर के हिमालय भू भाग पर कब्जा हो चुका है तथा खाली में १६८५ से १६६२ तक न्यू मूर तीवू बंग्लादेश ने तीन बीघा २३,५०० वर्ग किलो मीटर ले चुका है व भारत ने अपना जमीन खोनी पडी थी तथा इन तमाम कार्य को बचावा देने की उदहस्य से आगामी २१ को इन आए हुऐ टिम ने भारत भूटान सीमा के सीमा के निरक्षन करेंगे बोल कर बताया है। जब कि इस फिन्स ने भारत के विभिन्न सीमा निरक्षन करेगें तथा जो इस भूटान क्षेत्र को निरक्षन के लिए १७ लोग के टोली ने निरक्षन कर ने कि जिम्मेवारी में जाने की जानकारी दी है। जबकि भारत में शहीद देश की अमूल्य धरोहर होते है सीमा पर सैनिक एक रक्षक है तो वहां के नागरिको की भी जिम्मेदारी होती है, जो उन तमाम सभी को देश के माटी के जमीन के कीमत के बारे में जानकारी कराना है जा आज आए १७ जन के टोली ने सिमा क्षेत्र के लोगो को सीमा में रक्ष करना वा विदेशी तमाम सीमा में अति क्रमन से बचाने की तमाम जानकारी दी जा रही है तथा उन सीमा क्षेत्र के लोगों के दुःख तकलीफ आदि समस्या की भी जानकारी लिखकर ले जाया जा रहा है जो आगामी दिनों में सरकार वा स्थान जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाऐगा बोल कर बताया गया। तथा इस सीमा क्षेत्र के निरक्षन करने का प्रमुख कारण विगत भारत १६४६ में स्वाधिन होने के समय ३२ लाख ८७ हजार वर्ग किलो मीटर था, जो आज २०१२ तक घट कर ३१ लाख वर्ग किलो मीटर हो गया है। जो आजादी के ६५ सालों में भारत के १ लाख ८७ हजार वर्ग किलोमिटर भारत के उन पडोसी देशों ने कब्जा कर चुका है जिस को बचाना भारत के हर तमाम नागरिक को जागरुक के साथ जगाने का काम कारण से यह कार्यक्रम किये जाने का जानकारी दी है। जब कि उन निरक्षन करने वाले टिम ने वतन की रक्षा करो, भारत माता की जय, एवं वदे मातरम के नारे गुंजाते सीमा के अंतराष्ट्रीय पिलर की देख ते गंगा जल छूट ते भारत भूटान के सीमा को सुध करे दिखाइ दिया । अन्त आज के दिन में भूटान गेट के सामने उन संगठन ने स्थानीय जनता को लेकर मानव श्रृंखला का कार्यक्रम के साथ भारत माता के जय जय की नारे गंजाया और भारत के सीमा एंव भारत माता की रक्षा को लेकर नारे लगाकर जय गांव का परिक्रम की गया। जलपाईगुडी जिला के लिए इस तरह कार्यक्रम हो रहा बोल कर सूचना नही है जबकि उन्होंने बाहर से आऐ है।

Newspaper Association of India 20th Annual Conference and National Achievement Award-2012 on 29th December

❑ NAI DESK

Newspapers Association of India (NAI) which represents the press at the grassroots level in almost all languages and territories of the country, and which constitutes the core of the press community in this country since its inception in 1993, has endeavored to bring the Small and Medium newspapers and media organization from the length and breadth of our great country together under the ambit of one platform . Until now we were successful in bringing together approximately 7000 such entities as active members under our umbrella. These newspapers are published in Hindi, English and other vernacular languages. Together they enjoy a reach to every nook and corner of the country. Our association actively takes up matters relating to the difficulties being faced by the publishers of these newspapers and also disseminates information useful to them from time to time. The Conference would be focusing on the role that the regional newspapers play in the strengthening of this World's largest democracy. The emphasis would be on how the regional newspapers strengthen our democratic institutions with adherence to secular credentials. The strength of our democracy lies in the dissemination of information and these regional and vernacular language newspapers with their reach deep in the hinterland can and plays an effective role in the propagation of democratic ideas and advantages of people power.

Publishing on 10th of every month
RNI No. 62500/95
REGD. No. DL (E)-01/5149/2012-2014
LICENCE TO POST WITHOUT
PRE-PAYMENT No. U(C)223/12-14

To,

If undelivered, Please return to:
न्यूज़ पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया
POST BOX 9235, NEW DELHI-110 092

यदि आप लेख, रचना, समाचार, विचार प्रेषित करना चाहते हैं तो आप अपने अप्रकाशित लेख निम्न पते पर भेजें।

आपको ***NAI*** का यह अंक कैसा लगा, इस बारे में अपने सुझाव हमें निम्न पते पर भेजें।

एन. ए. आई.
A-115, Vakil Chambers, Top Floor,
Shakarpur, Delhi-110092, Ph.: 011-22058133

Editorial Board

Founder	Late Dr. M. R. Gaur
Editor Publisher-Printer	Vipin Gaur
Counsultant Editor:	Dr. Smita Mishra
Managing Editor:	Dilip Kumar
Legal Advisors:	Nikhat Anjum Malik
Advocate Delhi Highcourt	Rajesh Sharma
	Adv. P. Yadav
Office Secretary	Kavita Bamotra

- Bureau Chief -

Guwahati:	Runu Hazarika
Mumbai:	Mr. Dinesh K. Mishra
Bangalore:	Mr. M. K. Jain
Jaipur :	Mr. Banwar Singh Ranawat
Chennai:	Mr. P.C.R. Suresh
M.P. & C.G.	Mr. O. P. Jain
Kerela	Mr. Suvarna Kumar
Goa	Dr. Vivek Gaitonde

न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन 29 दिसम्बर को

❑ एनएआई डेस्क

न्यूजपेपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के द्वारा पत्रकारिता व सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र मे, एनएआई पुरस्कार 2012 के लिए न्यूजपेपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया का राष्ट्रीय सम्मलेन।

न्यूजपेपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया भारत के पत्रकारों व समाज सेविओं को आमंत्रित करता है जिनका सहयोग भारत को विकासशील और प्रगतिशील बनाने मे रहा है और उन कार्यों को लेख , समाचारपत्र , वीडियो, तस्वीरों , सामाजिक गतिविधियों, द्वारा प्रकाशित व प्रसारित किया हो व कृषि व ग्रामीण विकास के कार्यों मे अपना सहयोग दिया हो हर साल की तरह इस साल भी न्यूजपेपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया भारत के पत्रकारों व समाज सेवियों को पुरुस्कार से सम्मानित करेगा न्यूजपेपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया १६ सालों से पत्रकारों की सेवा करने व उनकी समस्यों का समाधान करने पे लगी है पत्रकारिता के क्षेत्र मे कार्य करने वाले लोग देश की जनता की समस्या को सामने लाते है पर अपनी समस्या को किसी से नहीं बताते हैं उन पत्रकारों व समाज सेवियों को सलाम व सम्मान आप अपने प्रकाशित लिखा लेख, समाचार, वीडियो, तस्वीरें, सामाजिक गतिविधियों, कृषि व ग्रामीण विकास पर लघु फिल्म हमे भेजें यदि आप 2012 एनएआई पुरस्कार कार्यक्रम में भाग लेने में रुचि रखते हैं, तो कृपया अपने पोर्ट फोलियो भेजें. सीडी या मेल कर सकते हैं: –naiindia@gmail.com हमारी वेबसाइट मे सारी जानकारी www-naiindia.com

इस पुरस्कार कार्यक्रम मे देश के 24 राज्यों के संपादक, प्रकाशक, पत्रकार हिस्सा लेंगे समाचार पत्रों व समाचार जगत मे कार्य करने वाले संपादको, प्रकाशकों, पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी व उनका समाधान कैसे किया जाए सभी सवालों को सरकार के सामने रखा जाएगा व उन सभी समस्यों को हल करने की मांग की जाएगी देश के संविधान की मर्यादा के पालन को लेकर सामाजिक हितो की राष्ट्रीय आवाज बनाने मे लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप मे इस मीडिया शक्ति से बड़ा कोई भी लोकपाल वैकल्पिक जवाबदेही नहीं निभा पा रहा है जिसे जनतंत्र की आवाज कहा जा सके। समाचार पत्रों के प्रतिनिधि समाज प्रहरियों की भूमिका ने है देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आजतक भारत को विश्व सचेतक बनाने की मंजिल को आसन रास्ता दिया है। मीडिया ने राजनैतिक कुशलता प्रोत्साहित करने मे कई सहायिक कदम उठाए है। इस समारोह मे मीडिया के हको की आवाज को उठाने के साथ साथ मीडिया प्रहरिओं की सुरक्षा के लिए राज्यों की नीतिओं के बदलाव के लिए भी जोर दिया जाएगा।

न्यूजपेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 20वे राष्ट्रीय अधिवेशन समारोह का विवरण

पहला सत्र	दूसरा सत्र	तीसरा सत्र
मुख्यअतिथि **श्री निनोंग इरिंग** (माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय)	मुख्य अतिथि **श्री सचिन पायलट** (माननीय कार्पोरेट मामलों के केन्द्रीय मंत्री)	मुख्य अतिथि **श्री हरीश रावत** (माननीय जल संस्थान मंत्री)

विशेष अतिथि

श्री सुनील डांग (मुख्य सम्पादक, डे आफ्टर)
श्री संदीप मारवाह (डायरेक्टर ऑफ ए.एस.एम.एस)
डॉ. ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन (डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल फोर प्रमोशन ऑफ ऊर्दू लेंग्वेज़)
डॉ. स्मिता मिश्रा (कंसलटेंट एडिटर, एन.ए.आई.)

कार्यक्रम के प्रायोजक:–
radio noida 107.4MHz Community Radio
नंददर्शन
day after
Panchayat Ujala National weekly
Country and Politics
Akash Jyothi (National Hindi Daily)

Printed, Published by Vipin Gaur on behalf of News papers Association of India, Printed at Mayank Offset Process 794/95 Guru Ramdas Nagar Ext. Laxmi Nagar Delhi-92 and Published from J-51, DLF Dilshad Delhi-95, Editor: Gayatri Gaur. All disputes settled in Delhi Court only.